eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 01, Jan 2018

डिजिटल इंडिया और भारतीय कार्य संस्कृति

[1]डा0 पप्पी मिश्रा
[1]एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिक शास्त्र, डी.जी. कालेज, कानपुर

Received: 01 Jan 2018, Accepted: 15 Jan 2018 ; Published on line: 31 Jan 2018

Abstract

किसी समाज के सदस्यों में भावात्मक प्रेरणाओं बौद्धिक क्षमताओं और नैतिक परिप्रेक्ष्यों के रूप में समान मानव प्रकृति होती है। यह समान मानव प्रकृति किन्ही मूल्यों विश्वासों और भावात्मक अभिकृतियों के रूप में अपने आपकों अभिव्यक्ति करती है। जो कामोबेश संशोधनों के साथ एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक सम्प्रेषित की जाती है और इस प्रकार किसी समाज की समान संस्कृति की रचना होती है इसी प्रकार किसी समाज की सामान्य संस्कृति के कई पहलुओं का सम्बन्ध इस बात से होता है कि सरकार किस प्रकार चलाई जानी चाहिये और इसे क्या करने की कोशिश करनी चाहिए। संस्कृति के इस क्षेत्र को हम राजनीतिक संस्कृति कहते है।

शब्द संक्षेप– डिजिटल इंडिया, संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति और भारतीय कार्य संस्कृति।

Introduction

किसी भी राष्ट्र की सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति से इस बात का संकेत मिलता है कि उस राष्ट्र की कार्य संस्कृति कैसी है। जब हम भारतीय संस्कृति पर दृष्टि डालते है। तब हम देखते कि भारतीय संस्कृति का आज भी विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकत्रान्तिक एवं धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है यहाँ सभी वर्गों एवं धर्मों के लोग रहते है शायद यही कारण है कि भारत विविधताओं में भी एकता को समेटे हुये है और यही भारतीय संस्कृति विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए हैं लेकिन केवल पहचान बनाना ही भारत के लिये काफी नहीं है बल्कि एक विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत अपनी पहचान बनाये इसके लिये अकारणों को खोजना होगा जिससे भारत एक अलग पहचान बनाये। क्या वर्तमान प्रधानमंत्री का यह सपना डिजिटल इण्डिया विश्व में एक नई कार्य संस्कृति की पहल है निश्चित रूप से शासन और प्रशासन जब भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और उसकी जवाब देही को तय करेगे इस दिषा में अवष्य परिवर्तन आयेगा। शासनस्तर में पारदर्शिता होना आवश्यक है जो नागरिकों की विश्वसनीयता को बढ़ायेगा।

डिजिटल इंण्डिया कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से आम लोगों का जीवन आसान करना। इसके नौ स्तम्भ है जो लोगों के जीवन स्तर को सुखद मोड़ देने की ताकत रखते है। जैसे कि ई गवर्नेन्स–तकनीक के माध्यम से प्रशासन में सुधार आया। पिछले कुछ वर्षों से महसूस किया गया कि सूचनाओं के संप्रेषण से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, लोग अपने अधिकार के प्रति सजग हुये है। आम जनता के हित में केन्द्र और राज्य सरकार की बहुत सारी कल्याण कारी योजनाए चल रही है। इस कार्य संस्कृति से राष्ट्र में सरकारी कार्य क्षेत्रों में काफी परिवर्तन आया। ई फाइलिग से समय की बचत एवं भष्टाचार पर नियन्तरण किया जा सकता है। प्रषासन एवं शासन व्यवस्था में

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 01, Jan 2018

पारदर्षता तथा प्रशासन की जवाब देही को तय किया जा सकता है। य़द्यपि भष्टाचार एवं लाल फीताशाही के कारण और अपने अधिकार के विशय में सूचना के आभाव के कारण लोगों को इसका वास्तविक लाभ नही ंमिल पा रहा है। ज्यादातर पैसा उन लोगों तक नहीं पहुँचपाता जो कि वास्तव में उन योजनाओं से जुड़े लोगों के लिये बनायी गई। अर्थात जो उसके हकदार है। यदि सूचनाओं को डिजिटल कर दिया जाय और संप्रेषण को आसान बना दिया जाये। तब सरकार द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न कल्याण कारी योजनओं का लाभ जनता को मिल सकता है। जैसे ग्राम पंचायत द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों जैसे मनरेगा इंदिरा आवास योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली मध्यान्ह भोजन आदि ऐसी योजनाए हैं जो गॉवों में चलाई जाती है। शिक्षा से लेकर गरीबी उन्मूलन तक विकास की लगभग 29 से अधिक योजनाए हैं जिन्हें लागू करने के लिये पंचायतों पर निर्भर है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इनमें खर्च की जानेवाली राशि और होने वाले काम के विषय में जानकारी होगी तभी वह अपने अधिकार मॉग सकते है। यदि हर पंचायत में इन्टरनेट हो उसकी अपनी बेवसाइट हो, उस बेवसाइट में गॉव पंचायत से जुड़ी सभी सूचनाओं योजनाओं उनके निष्पादन की स्थित का वर्जन हो तो गॉवों को इससे फायदा होगा।

भारत विश्व एक ऐसा देश बन गया है। जिससे डिजिटल प्रौद्योगिक का प्रयोग सेवाए प्रदान करने सरकार से मिलने वाले लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते मे ंपहुॅचाने के लिये बहुत सफलता हासिल की आधार संख्या सृजित करके प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत पहचान दी। इससे जटिल सूचना समस्याओं को सुलझाने में सहायक मिल है केन्द्र सरकारें एवं राज्य सरकारें आधार संख्या के आधार पर अब तक लाभों से वंचित लोगों के समावेशन का कार्य कर रही है। डिजिटल इण्डिया से समाज को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है।